एसआईआर और ईवीएम के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

ज्ञानेश कुमार को हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

गुना, (एजेंसी)। गुना एसआईआर और ईवीएम से मतदान के विरोध में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह के मार्गदर्शन में प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश शर्मा ने हुंकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए पूरी क्षमता के साथ मैदान में डटी हुई है। उन्होंने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन १३ करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, यदि वे वास्तव में अपात्र हैं तो उनकी पारदर्शी सूची सार्वजनिक की जाए। वहीं, जो नागरिक पात्र हैं, उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव प्रणाली में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर बैलेट पेपर से वोटिंग करानेकी भी पुरजोर मांग उठाई।

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की सख्त मांग की है।

इसके अलावा, गुना जिले की स्थानीय मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बरती गई अनियमितताओं और विवादास्पद प्रक्रियाओं को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि जिले में फार्म-७ का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश रची गई है।

कांग्रेस ने मांग की है कि फार्म-७ का दुरुपयोग कर नाम हटाने के लिए दी गई सभी आपत्तियों और शिकायतों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। जानबूझकर झूठी शिकायतें दर्ज कराने, फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जाए। पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने के लिए जिम्मेदार दोषी शिकायकर्ताओं पर कानून के अनुसार सख्त और दंडनीय कानूनी कार्रवाई की जाए।

बीफार्मा की ७,३६१ और डीफार्मा की ८,१७० सीटें खाली

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में फार्मेसी पाठयक्रमों में प्रवेश की स्थिति इस सत्र में चिंताजनक रही है। प्रदेश के ५७ फार्मेसी कॉलेजों में अब तक एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है। वहीं, बीफार्मा की ७,३६१ और डीफार्मा की ८,१७० सीटें खाली रह गई हैं। इन रिक्त सीटों को भरने के लिए अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) राउंड शुरू किया गया है। जानकारी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में विद्यार्थी संबंधित कॉलेजों से संपर्क कर उपलब्ध सीटों की जानकारी ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को पहले के काउंसलिंग राउंड में सीट नहीं मिली या जो प्रवेश लेने से चूक गए, उनके लिए सीएलसी राउंड के जरिए दाखिले का अवसर है। सीटों की बड़ी संख्या में रिक्तता और ५७ कॉलेजों में शून्य प्रवेश से फार्मेसी संस्थानों में विद्यार्थियों की कम रुचि सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रवेश कम होने के कारणों का विवरण नहीं दिया गया है। अब सीएलसी राउंड के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि खाली सीटों में से कितनी भरी जा पाती हैं।

बजट में हर मांग की होगी पड़ताल

मध्यप्रदेश के २०२७-२८ बजट की तैयारी में वित्त विभाग सख्त, विभागों को बताना होगा खर्च का हिसाब, जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर तय होगा राशि का प्रावधान

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के आगामी बजट में विभागों की मांग के मुताबिक राशि आवंटित करना आसान नहीं होगा। वित्त विभाग अब प्रस्तावों की जरूरत, उनकी लागत और प्राथमिकता को बारीकी से परखने की तैयारी में है। वित्तीय वर्ष २०२७-२८ के बजट के लिए विभागवार चर्चा का पहला दौर पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में चुनिंदा प्रस्तावों की दोबारा समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया में विभागों को अपनी मांग के औचित्य और प्रस्तावित खर्च की जरूरत स्पष्ट करनी होगी।

बजट चर्चा के पहले चरण में वित्त विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के उप सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठकें कर योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए मांगी गई राशि पर विचार किया। अब दूसरे चरण में उन प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनके लिए अधिक विस्तार से आकलन की जरूरत है। वित्त विभाग यह समझने का प्रयास करेगा कि संबंधित योजना या काम के लिए वास्तव में कितनी राशि जरूरी है और बजट में कितना प्रावधान किया जाना चाहिए।

मांग नहीं, जरूरत के आधार पर तय होगी प्राथमिकता

दूसरे चरण की चर्चा में केवल विभागों की मांग दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्तावों की उपयोगिता, उनकी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर बजट में जगह देने पर विचार किया जाएगा। इससे विभागों के बीच उपलब्ध संसाधनों के बंटवारे को लेकर वित्त विभाग की भूमिका अहम हो जाएगी। जिन प्रस्तावों के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है, उनके औचित्य और आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा होगी। यह चरण नवंबर के मध्य तक चलेगा। इसके बाद विभागों से मिले प्रस्तावों और बैठकों में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर बजट प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे सचिव स्तर पर भी बजट चर्चा प्रस्तावित है, जबकि जनवरी में वित्त मंत्रीके स्तरपर विभागवार बैठकें होंगी।

अनुपूरक बजट के प्रस्ताव भी मांगे

इधर, वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्ताव २२ अक्टूबर तक आईएफएमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भेजे जाएं। विभागों ने प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है।

बजट की तैयारी का आगे का कार्यक्रम

२०२७-२८ के बजट पर दूसरे चरण की चर्चा नवंबर मध्य तक होगी। उसके बाद १६ नवंबर से १४ दिसंबर तक सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ तीसरे चरण की बैठकें होंगी। वहीं १५ से ३१ जनवरी २०२७ तक वित्त मंत्री के स्तर पर विभागवार बजट बैठकें होंगी। १५ जनवरी बजट भाषण के लिए विभागों से जानकारी भेजने की अंतिम तिथि है। ३१ मार्च पुनर्विनियोजन, समायोजन और प्रत्यर्पण संबंधी आदेश वित्त विभाग को भेजने की अंतिम तिथि है। बजट तैयार करने की इस प्रक्रिया में विभागों की वित्तीय जरूरतों और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। अब देखना होगा कि समीक्षा के बाद किन योजनाओं को अतिरिक्त राशि मिलती है और किन प्रस्तावों को प्राथमिकता के क्रम में पीछे रखा जाता है।

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर लगाया स्टे

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया गया है। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रकरण की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर किये जाने को लेकर ट्विशा के पिता और शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा ने याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर विपक्षी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। याचिका में मांग की गई है कि भोपाल में चल रहे मामले को दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर किया जाए, ताकि सुनवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर बहस होनी थी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस कारण १६ अक्टूबर को जमानत पर बहस नहीं हो सकी। अब २६ अक्टूबर को सुबह १०:३० बजे सुनवाई होगी। हालांकि गिरिबाला सिंह के वकील का कहना है की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखना चाहते थे, इसलिए जमानत पर बहस के लिए २६ अक्टूबर की तारीख तय की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को जमानत अर्जी पर कोई बहस नहीं हुई। उल्लखनीय है की सीबीआई ने चार्जशीट में दहेज मृत्यु से संबंधित आरोप हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप शामिल किया गया है। इसके बाद गिरिबाला सिंह की ओर से जमानत आवेदन में संशोधन की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आवेदन में बदलाव की अनुमति दी थी, ताकि बदले हुए आरोपों के आधार पर जमानत पर बहस हो सके।

ट्विशा शर्मा (३३) का शरीर १२ मई २०२६ को भोपाल स्थित अपनी ससुराल में फंदे पर लटका मिला था। उनकी शादी ९ दिसंबर २०२५ को समर्थ सिंह से हुई थी। मौत के बाद उनके परिजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शुरुआत में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु, क्रूरता और दहेज प्रतिषेध कानून के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रकरण में भोपाल की जिला अदालत ने १५ मई को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी। लेकिन मृतका के परिजन और राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद २७ मई को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी। इसके बाद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को जांच के दौरान हिरासत में लिया गया।

संसाधन तैयार, सिस्टम लाचार, अपराध की वैज्ञानिक जांच पर ब्रेक

मशीनें खरीदने में करोड़ों खर्च, चलाने की तैयारी गायब; ५७ में से २९ फोरेंसिक वैन बेकार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में अपराधों की वैज्ञानिक जांच मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर संसाधन जुटाए गए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जरूरी मानव संसाधन ही नहीं जुटाया जा सका। नतीजा यह कि अपराध स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने के लिए तैयार की गईं फोरेंसिक वैन सडक़ पर दौडऩे के बजाय पुलिस लाइन के गैराज में खड़ी हैं। यह स्थिति सिर्फ सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि अपराध अनुसंधान को आधुनिक बनाने की तैयारी की जमीनी हकीकत भी सामने लाती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से करीब ३७ करोड़ रुपये की लागत से मिलीं ५७ चलित फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में से २९ का नियमित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनके संचालन के लिए महज २७ वैज्ञानिक अधिकारी हैं और १९ जिलों में २८ वैन ही काम कर रही हैं। यानी जिन संसाधनों को प्रदेशभर में वैज्ञानिक जांच की पहुंच बढ़ानी थी, उनका बड़ा हिस्सा विशेषज्ञों की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ा है।

खरीद पहले, संचालन की तैयारी बाद में

इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि जब वैन की खरीद और वितरण की योजना बनाई गई, तब उनके संचालन के लिए जरूरी वैज्ञानिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? प्रति वैन लगभग ६५ लाख रुपये की लागत से खरीदी गई इन प्रयोगशालाओं को दिसंबर २०२५ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद भी पर्याप्त विशेषज्ञों के अभाव में वैन कई महीनों तक मुख्यालय में खड़ी रहीं। सितंबर २०२६ में इन्हें जिलों में भेजा गया, लेकिन वहां भी संचालन की समस्या दूर नहीं हो सकी। यह क्रम सरकारी कार्यप्रणाली की उस कमजोरी की ओर इशारा करता है, जिसमें मशीनें और उपकरण जुटाने को ही व्यवस्था तैयार कर लेने के बराबर मान लिया जाता है। जबकि किसी तकनीकी सुविधा की वास्तविक उपयोगिता उसके नियमित संचालन, प्रशिक्षित कर्मचारियों, रखरखाव और जवाबदेही से तय होती है।

सात साल की सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य अहम

भारतीय न्याय संहिता और नई आपराधिक न्याय व्यवस्था के तहत सात साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसके लिए हर पुलिस अनुविभाग में चलित फोरेंसिक प्रयोगशाला की जरूरत बताई गई है। योजना के मुताबिक, राज्य सरकार को १७४ और केंद्र सरकार को ५७ वैन उपलब्ध करानी थीं। ऐसे में केंद्रीय सहायता से मिली वैनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाना व्यवस्था की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। फोरेंसिक जांच केवल अपराध स्थल की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं है। खून, बाल, डीएनए, फिंगरप्रिंट, गोली चलने के अवशेष और दूसरे वैज्ञानिक साक्ष्य जांच की दिशा तय कर सकते हैं। साक्ष्य समय पर और सही तरीके से जुटाए जाएं तो जांच को मजबूती मिल सकती है।

इसके विपरीत, विशेषज्ञों की अनुपलब्धता या प्रक्रियागत देरी से वैज्ञानिक जांच की पूरी क्षमता हासिल करना कठिन हो जाता है।

उपकरण मौजूद, विशेषज्ञों का इंतजार

इन वैनों में स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डिजिटल कैमरा, वेइंग बैलेंस, थर्मल प्रिंटर और दूसरे तकनीकी उपकरण उपलब्ध हैं। इनके साथ फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल, खून, नशीले पदार्थों, विस्फोटकों और आगजनी से जुड़े साक्ष्य जुटाने की किट भी दी गई हैं। गोली के निशान और पैरों या टायरों के निशान की जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी इनमें शामिल हैं। लेकिन उपकरणों की मौजूदगी अपने आप में वैज्ञानिक जांच की गारंटी नहीं है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ के बिना इनका सही उपयोग, साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन और निर्धारित

दुकानों पर असली की जगह चिपका रहे फर्जी क्यूआर

क्यूआर कोड स्कैन करते समय बरतें सावधानी, साइबर ठगों का नया पैंतरा

भोपाल, (एजेंसी)। डिजिटल भुगतान के इस दौर ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, साइबर ठगों ने उतनी ही तेजी से ठगी के नए और खतरनाक रास्ते भी तलाश लिए हैं। अब धोखाधड़ी के लिए केवल फर्जी फोन काल या ओटीपी ही नहीं, बल्कि आपका एक छोटा सा गलत स्कैन आपकी कमाई को पलभर में साफ कर सकता है।

दरअसल, क्यूआर कोड से जुड़ा यह नया जाल ठगी का माध्यम बन गया है। इस संबंध में ग्वालियर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ग्वालियर में इस तरह का एक मामला साइबर क्राइम विंग के पास पहुंचा है, जिसमें दुकानदार को किया गया भुगतान ठगों के पास पहुंच गया।

इस तरह हो रही क्यूआर कोड से ठगी

दुकानों पर असली की जगह नकली क्यूआर कोड चिपकाना : सामने आया है कि ठग रात के अंधेरे या भारी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर नामी दुकानों, पेट्रोल पंपों और पार्किंग स्थलों पर लगे असली क्यूआर कोड के ऊपर अपने क्यूआर कोड का स्टीकर चिपका देते हैं। ग्राहक खरीदारी के बाद जब भुगतान करने के लिए इस कोड को स्कैन करता है, तो पैसा दुकानदार के पास पहुंचने के बजाय सीधे ठग के खाते में चला जाता है।

इनाम, लाटरी और कैशबैक का लालच

अक्सर मोबाइल पर ऐसे लुभावने संदेश आते हैं- बधाई हो! आपने ५०,००० रुपये का इनाम जीता है, तुरंत नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और पैसे पाएं। वाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के जरिए भेजे जाने वाले इन संदेशों का एकमात्र उद्देश्य लोगों को झांसे में लेना होता है। जैसे ही कोई लालच में आकर कोड स्कैन करता है, उसके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं।

मोबाइल हैक और फिशिंग लिंक

कई बार फर्जी क्यूआर कोड खतरनाक फिशिंग वेबसाइट्स या मालवेयर अटैक का जरिया बनते हैं, जिससे पीडित का पूरा मोबाइल फोन हैक हो सकता है और पर्सनल डाटा तक चोरों के हाथ लग सकता है।

खंडहर में ले जाकर बेरहमी से की गयी मासूम बच्ची की हत्या

रात से थी लापता, सुबह मिली लाश, अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

भोपाल, (एजेंसी)। शहर के उपनगर बैरागढ़ इलाके में कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक वीरान खंडहर में करीब १२ साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या किये जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया गया है की मासूम रात से लापता थी, उसकी लाश सुबह के समय खंडहरनुमा मकान में मिली। पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक मासूम मृतका बैरागढ़ फाटक रोड स्थित झुग्गी बस्ती में परिवार के साथ रहते हुए पन्नी बीनने का काम करती थी। परिजनों ने बताया कि मासूम गुरुवार रात करीब ८ बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। आसपास के इलाके सहित परिचितो में उसकी काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसकी कोई जानकारी नहीं लगी तब देर रात परेशान परिवार वाले बैरागढ़ थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। शुक्रवार को सुबह बच्ची की लाश खंडहर में मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया ओर थाना पुलिस सहित एफएसएल टीम और आला अफसर भी मौके पर पहुंच गये। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने खंडहर की बारीकी से छानबीन कर अहम जुटाये है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिये भेज दिया है, वहीं अज्ञात आरोपी का सुराग जुटाने के लिये टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाल रही है। वहीं इस बिंदु की जानकारी जुटाई जा रही है कि मासूम बच्ची रात के समय खंडहर तक कैसे पहुँची और अंतिम समय वह किसके साथ नजर आई थी। अफसरो का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वहीं मासूम की हत्या किस तरह की गई और हत्या से पहले उसका शोषण तो नहीं किया गया इसका खुलासा पीएम रिर्पोट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस घटना स्थल से जुटाये गये सुरागो के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

बहू से दुष्कर्म के आरोपी जेठ को १० साल की जेल

भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की एक अदालत ने बहू के साथ बलात्कार के मामले के आरोपी शाकिर शाह (३०) निवासी ग्राम निपान्या चैतन्य राजगढ़ को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए १० साल के कठोर कारावास और ४ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने १ जून २०२० को राजधानी के थाना कोलार रोड में शिकायत करते हुए बताया था कि उसका विवाह नरसिंहगढ़ राजगढ़ में हुआ था। उसका ट्रक ड्राइवर पति काम के चलते आये दिन घर से दूर रहता था। पति के बाहर रहने के कारण उसका जेठ उस पर बुरी नियत रखते हुए अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता था। जेठ की हरकतों से तंग आकर वह अपने पति के साथ राजधानी के कोलार रोड पर आकर रहने लगी थी। आरोप था की ५ नवंबर २०१९ को उसका पति काम पर गया था, इसी दौरान उसके जेठ ने घर में घुसकर उसके साथ ज्यादती की थी। समाज में बदनामी के उर के कारण विवाहिता ने उसकी करतूत के बारे में किसी को नहीं बताया। उसके चुप रहने से आरोपी की हिम्मत बढ़ गई और आरोपी जेठ ने २२ मई २०२० तक कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। जेठ की करतूतों से तंग आकर विवाहिता थाना कोलार रोड पहुचीं जहॉ फरियादिया की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्जकर मामले की जांच के बाद जिला अदालतमें चालान पश किया था।

आबकारी से सरकार की कमाई सबसे ज्यादा बढ़ी

इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में राजस्व संग्रहण में ११.३७ प्रतिशत की बढ़ोतरी

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में राजस्व संग्रहण में ११.३७ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर २०२६ के बीच वाणिज्यिक कर, आबकारी और पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों ने कुल ४४,७११ करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा ४०,१४७ करोड़ रुपये था। इस तरह एक साल में इन तीनों विभागों का राजस्व संग्रहण ४,५६४ करोड़ रुपये बढ़ा है। इसमें भी आबकारी विभाग के कर संग्रहण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तीनों विभागों ने छह महीने के लिए तय ४७,४३९ करोड़ रुपये के लक्ष्य का ९४.२५ प्रतिशत हासिल कर लिया है।

वित्तीय वर्ष पूरा होने में अभी छह महीने बाकी हैं। इस अवधि में शेष लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागों को कुल २,७२८ करोड़ रुपये और जुटाने होंगे। तीनों विभागों में वाणिज्यिक कर विभाग का राजस्व संग्रहण सबसे ज्यादा रहा। विभाग ने अप्रैल से सितंबर तक ३०,६८६ करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले २८,३८५ करोड़ रुपये जुटाए। यह लक्ष्य का ९२.५० प्रतिशत है। पिछले साल इसी अवधि में विभाग ने २६,०५२ करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। इस बार इसमें ८.९६ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आबकारी विभाग लक्ष्य के सबसे करीब

आबकारी विभाग ने छह महीने में ९,९०० करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले ९,७६९ करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। विभाग ने लक्ष्य का ९८.६८ प्रतिशत हासिल कर लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ८,२९५ करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इस बार संग्रहण में १७.७७ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तीनों विभागों में आबकारी विभाग लक्ष्य पूरा करने के सबसे करीब है।

पंजीयन-मुद्रांक से ६,५५७ करोड़ मिले

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ६,८५३ करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले ६,५५७ करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। यह लक्ष्य का ९५.६८ प्रतिशत है। पिछले साल इसी अवधि में विभाग ने ५,८०० करोड़ रुपये जुटाए थे। इस बार राजस्व संग्रहण में १३.०६ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर में ९६ प्रतिशत से अधिक वसूली

मासिक आंकड़ों में अप्रैल का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस महीने तीनों विभागों ने संयुक्त रूप से ७,४११ करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले ७,९३८ करोड़ रुपये जुटाए। यह लक्ष्य का १०७.११ प्रतिशत है। पिछले साल अप्रैल की तुलना में राजस्व संग्रहण में ३५.७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर में तीनों विभागों ने ६,९३६ करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले ६,६७६ करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। यह लक्ष्य का ९६.२५ प्रतिशत है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस बार संग्रहण १२.८९ प्रतिशत अधिक रहा

क्या दतिया में फिर होगा उपचुनाव?

१९९१ के पुराने मामले में फंसे कांग्रेस विधायक, हाईकोर्ट से मिला नोटिस

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है। नोटिस के बाद दतिया की राजनीति में संभावित उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामला वर्ष १९९१ में कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई एफआईआर से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान घनश्याम सिंह समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय घनश्याम सिंह ने इस आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी। इसी मुद्दे को लेकर दीपक बेलपत्री समेत कुछ लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इसी मामले में अदालत ने विधायक घनश्याम सिंह को नोटिस जारी किया है। हालांकि सिर्फ नोटिस जारी होना आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। मामले में अदालत की आगे की सुनवाई और अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अवधेश नायक ने कहा कि हाईकोर्ट से नोटिस मिलना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और फिलहाल इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं नायक ने बीजेपी नेता राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजेंद्र भारती की भूमिका हो सकती है।

खेलो इंडिया सेंटर राजगढ़ के खिलाड़ियों ने ६ स्वर्ण एवं ४ कांस्य पदक जीते

राजगढ़, (एजेंसी)। स्कूल स्टेट जूडो चैंपियनशिप २०२६ में खेलो इंडिया सेंटर राजगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ६ स्वर्ण एवं ४ कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम गौरवान्वित किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस दौरान दोनों अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी सफलता की खुशी साझा की। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में साक्षी गुप्ता, मैना सोंधिया, कुश वजार, ज्योतिराज प्रजापति, पुष्पेंद्र भदौरिया एवं सुमित प्रजापति शामिल हैं। वहीं कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में दिक्षांत प्रजापति, भाविका गौर, मनीष जाटव एवं हरिओम प्रजापति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. गढ़पाले ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करने तथा जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। खेलो इंडिया सेंटर राजगढ़ में खिलाड़ियों को नियमित जूडो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

खिलाड़ियों की यह उपलब्धि उनके निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम और समर्पण को दर्शाती है। राज्य स्तर पर मिली इस सफलता से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है।

खेलो इंडिया सेंटर राजगढ़ का संकल्प है, खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयार करना, सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएँ।

क्राइस्ट स्कूल विवाद : लगातार दूसरे दिन हिंदूवादी संघटनों का उग्र प्रदर्शन, परिसर में पुतला फूंककर सौंपा ज्ञापन

गुना, (एजेंसी)। शहर के प्रतिष्ठित क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के दौरान एक नन्हीं छात्रा द्वारा राजनीतिक और सरकार विरोधी संदेश प्रदर्शित किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों और छात्र नेताओं ने विद्यालय परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिसर के भीतर क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन का पुतला फूंका और प्राचार्य को एक विस्तृत कानूनी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

प्राचार्य को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि १३ अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा के परिजनों द्वारा सुनियोजित तरीके से एक अबोध बालिका का दलगत राजनीतिक नारों एवं प्रचार सामग्री के लिए उपयोग किया गया, जो विधिक व नैतिक दृष्टि से गंभीर अपराध है। ज्ञापन में कहा गया कि यद्यपि प्रचार सामग्री अभिभावकों ने तैयार कराई, लेकिन इन लोको पैरेंटिस (अभिभावक सदृश) की भूमिका में होने के बावजूद स्कूल की स्क्रीनिंग समिति और जिम्मेदार शिक्षकों ने इसे मंच तक जाने दिया। यह विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही और राजनीतिक दबाव में दी गई मौन सहमति को दर्शाता है।

ज्ञापन में किशोर न्याय अधिनियम २०१५ की धारा ७५, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के दिशा-निर्देशों तथा सीबीएसई संबद्धता उपनियम २०१८ के विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी भी नाबालिग का राजनीतिक उपयोग गैर-कानूनी है। साथ ही विद्यालय परिसर की तटस्थता भंग करना सीबीएसई की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। हिंदू समाज एवं छात्र संगठन ने ७२ घंटे के भीतर कार्यक्रम प्रभारी व